वस्त्र उद्योग में महिलाओं की भागीदारी

305. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सिले-सिलाए वस्त्रों और कपड़ों का कुल निर्यात क्या रहा;

(ख) वस्त्र और कपड़ों के निर्यात के कार्य में लगी महिला उद्यमियों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात निम्नानुसार रहा:

वर्ष	मूल्य—अमरीकी मिलियन डालरों में
1995-96	4453.31
1996-97	4762.10
1997-98	4910.70

(ख) यद्यपि वस्त्र और परिधान निर्यात कार्य में लगी महिला उद्यमियों की संख्या अधिक नहीं है, फिर भी परिधान विनिर्माण कार्य में पर्याप्त संख्या में महिलाएं लगी हुई हैं।

(ग) हमारे निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से परिधानों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्पाद/संसाधन उन्मुख उद्योग शुरू करने के प्रति उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए लघु उद्योग विकास संगठन अपने विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों के लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा अनेक उद्यमी विकास कार्यक्रमों का आयोजन करता है। परिधान उद्योग पर उद्यमी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गहन प्रशिक्षण में सहभागियों को व्यापक ज्ञान प्रदान किया जाता है ताकि वे अपने उद्योग शुरू करने तथा निर्यात क्षेत्र में कार्य करने के लिए समर्थ हो सकें।

Rehabilitation of Ailing Textile Mills

306. SHRI K.M. SAIFULLAH: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state the steps proposed to rehabilitate the ailing textile mills in the country during the current year?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): A series of policy interventions have been made by the Government to strengthen the textile industry. Some of these are as follows:

1. Setting up of an Expert Committee for recommending a new Textile Policy;
2. Giving EOUs producing cotton yarn, flexibility to export such yarn without any count restriction;
3. Mooting a proposal to launch a Technology Upgradation Fund Scheme for Textile & Jute Industries to provide interest incentive to textile and jute units;
4. Mooting a proposal to launch a Cotton Technology Mission with a view to increasing productivity, improving research, marketing and post harvest activities;
5. Setting up of a task force for facilitating induction of Information Technology in the textile sector; and
6. Allowing import in certain circumstances of high grade quality mulberry raw silk; etc.

In addition, Ministry of Textile have been trying to persuade the financial institutions and banks to show some flexibility so that the credit needs of the textile units are met with least difficulties.

Export of Cotton Yarn

307. SHRI YADLAPATI VENKAT RAO: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state the steps taken to boost textile exports, particularly cotton yarn which had slowed down?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): Government have been taking a number of steps to boost exports of textile items, including cotton yarn, such as encouraging exporters to participate in buyer-seller meets, fairs and exhibitions; enabling import of capital goods at

concessional duty for export production, special arrangements for duty free import of raw materials, ensuring increased availability of export credit etc. Recently, the Government have annonced specific measures for boosting cotton yarn exports which include delinking of cotton yarn exports from hank yarn obligation; greater operational flexibility to 100% EOUs producing cotton yarn by way of relaxation of count/domestic cotton use restrictions etc.

Revival of sick Textile Mills

308. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up new textile mills in the country during the Ninth Plan;

(b) if so, the details thereof, State-wise, particularly in Gujarat; and

(c) the details of funds provided by Government to the State Governments for the revival of sick textiles mills during the current year and the Ninth Plan period, State-wise?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) and (b) There is no proposal before the Government to set up a new Textile mill in any part of the Country.

(c) Government of India does not provide funds to the State Governments for revival of sick textile mills.

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की ओर बकाया राशि

309. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम को समय-समय पर कपास की खरीद करने के लिए गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कपास संघ को कुछ बकाया राशि का भुगतान करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्यों की सरकारों ने केन्द्र सरकार को इस बकाया राशि का सीधा भुगतान किए जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) अगस्त, 1998 तक की स्थिति के अनुसार एन०टी०सी० द्वारा गुजरात राज्य कपास सहकारी समिति को कपास की देय बकाया राशि 14.81 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त 30.4.1998 तक की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य कपास सहकारी समिति और मध्य प्रदेश बीज निगम को क्रमशः 2.78 लाख रुपए और 1.93 लाख रुपए की राशि भी बकाया है।

(ग) और (घ) हाल ही में राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, सरकार को उपर्युक्त समितियों के बारे में इस आशय की जानकारी है कि वे बकाया देय राशि का भुगतान करने के लिए एन०टी०सी० को प्रतिवेदन कर रही हैं। चूंकि कपास उधार पर खरीदी जाती है इसलिए किसी भी समय कुछ बकाया राशि का होना स्वाभाविक है। कार्यशील पूंजी की जटिल कमी के कारण एन०टी०सी० ऐसी बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ है। एन०टी०सी० से ऐसी अपेक्षा है कि निधियों के उपलब्ध होने पर बकाया राशि का भुगतान हो जाएगा।

Textile Mill Project

310. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether various State Governments in consultation with Textile Unions have presented any project report named as Textile Mill Project to make provision of 150 crore rupees in the current budget to make these textile mills financially viable and for reviving them;

(b) if so, the details thereof, State-wise;

(c) whether this project has been cleared;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) the steps taken/being taken for the revival of these mills?